(c) Works are proceeding as per planned schedule drawn up for their completion.

(d) The cost escalation of the above projects are as under:—

i. Daund-Baramati	—Nil
ii Gondia-Chanda Fort (248 kms)	—Nil
iii Manmad-Aurangabad-Parbhani-Parli Vaijnath	—Rs 76.00 crores
iv Parbhani-Purna-Mudkhed-Adilabad and Purna-Mudkhed	—Rs 32.00 crores
v Miraj-Londa	—Nil

Priority to Transportation of Foodgrain and State Agro-Produce

2492. SHRI BHUPINER SINGH MANN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Railways would accord priority to transportation of foodgrains and other agro-produce from surplus States to deficit States for which facility is confined to State procurement agencies only;

(b) whether it is a fact that freight charges by road are four times higher as compared to the Railways; and

(c) if so, whether Railways would allow wagons for transportation to all, other than State agencies without delay?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K. C. LENKA): (a) Priority in allotment of wagons for goods traffic is accorded as per provisions of Preferential Traffic Schedule General Order No. 77. Foodgrains sponsored by Ministry of Food, Food Corporation of India and Ministry of Defence move under priority 'B' and when sponsored by State Govt. and State Agencies it is accorded priority 'C' Foodgrains on trade account when offered in full train loads is accorded priority 'D'. Important agro produce have been accorded to priority 'C'.

(b) It is likely that road rates may be higher between certain pairs of points and lower between others. Road rates could also differ from region to region.

(c) Traffic offered by traders and other than State agencies is also cleared subject to operational and route quota restrictions, priority and date of registration of indents.

अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा रेल यात्रियों को परेशान किया जाना

2493. **श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में यात्रा के दौरान अनधिकृत रूप से चाय और अन्य खाद्य पदार्थ बेचने वाले व्यक्ति दिनभर यात्रियों को परेशान करते रहते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) कुछ ऐसी घटनाएं नोटिस में आई हैं ।

(ख) अनधिकृत फेरी वालों/वेंडरों द्वारा गाड़ियों और स्टेशन परिसरों में फेरी लगाना/वस्तुओं को बेचना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 144 के अंतर्गत एक अपराध है । मूल रूप से यह एक सामाजिक-आर्थिक समस्या है । इस बुराई को नियंत्रित करने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस तथा रेलवे सुरक्षा बल के कार्मिकों की सहायता से रेलवे अधिकारियों द्वारा नियमित जांच की जाती है । इस प्रकार गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के विरुद्ध उस देश के कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है । जनवरी, 1993 से नवम्बर, 1993 तक की अवधि के दौरान अनधिकृत फेरी वालों/वेंडरों के खिलाफ 52192 बार जांच की गयी, जिनके परिणामस्वरूप 16624 व्यक्तियों पर मुकदमें चलाए गए, 2353 व्यक्तियों को जेल भेजा गया और जुर्माने के रुप में 19,13,572 रु० वसूल किए गए ।

गाड़ियों में निम्नस्तर का खाना आपूर्ति किया जाना

2494. **श्री विट्ठलराव माधव राव जाधव :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल गाड़ियों में आपूर्ति किए जाने वाले खाने का स्तर बहुत ही नीचे गिर गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार इसमें सुधार करने के लिए क्या कदम उठा रही है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बम्बई और दिल्ली के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस में दिये जाने वाले नाश्ते का स्तर बहुत ही खराब है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका स्तर सुधारने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेका) : (क) रेलें , भारतीय रेलों पर खान पान सेवाओं का संतोषजनक स्तर प्रदान करने की आवश्यकताओं के प्रति पूरी तरह सजग हैं । संबंधित मामले भी उठाए गए हैं और उन पर संसद सहित विभिन्न मंचों पर चर्चा की गई है ।

(ख) खान-पान सेवाओं में सुधार करना एक निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है । स्टेशनों और गाड़ियों में भोजन और मानक सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए रेलें निरंतर प्रयास कर रही हैं । कड़ी निगरानी के परिणामस्वरूप शिकायतों की संख्या भी घटी है । विभागीय खानपान यूनिटों को व्यावसायिक रसोइये लगाकर तथा जोरदार प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से और सक्रिय बनाया जा रहा है । ख्याति प्राप्त खानपान प्रबंधको द्वारा पहले से बनाया भोजन सप्लाई करने की एक अग्रिमगामी परियोजना शुरु करने के बारे में परिक्षण किये जा रहे है ।

(ग) पश्चिम रेलवे के अनुसार हाल ही में इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) प्रश्न नही उठता ।

Modernisation of Signalling System

2495. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Railways have embarked upon the modernisation of signalling system to meet the increasing demand of traffic, high-speed and additional safety bids;

(b) If so, what are the details in this regard;

(c) whether it is a fact that during 1992-93 large number of accidents took place due to the lack of facilities in signalling system;

(d) If so, what are the total signal centres in the various zones of the railways at present; and

(e) what is the amount likely to be spent for modernisation of the signalling system in the country?